भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1428
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोजगारी

1428. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डीः
श्री कल्याण बनर्जीः
श्री संतोख सिंह चौधरीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की हालिया रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान बेरोजगारी 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है और वर्ष 2019 में इसमें वृद्धि जारी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार अपने पिछले कार्यकाल में कोई भी रोजगार सृजित करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के भीतर देश में रोजगार और नौकरी उत्पन्न करने संबंधी प्रस्ताव क्या है तथा इसके लिए कार्य-योजना क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उद्योग और जनता पर, विशेष रूप से युवाओं पर, बढ़ती बेरोजगारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और देश में औपचारिक रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी युवाओं में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्य योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से छ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रमबल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार द्वारा हाल ही में जारी कर दी गई है। सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी की दर नीचे दी गई हैः

1972-73 से 2017-18 तक बेरोजगारी की दर (% में)				
सर्वेक्षण वर्ष	*ग्रामीण*		*शहरी*	
	पुरूष	*महिला*	*पुरूष*	*महिला*
2017-18* **(पीएलएफएस)**	**5.8**	**3.8**	**7.1**	**10.8**
2011-12 **(एनएसएस 68वां दौर)**	**1.7**	**1.7**	**3.0**	**5.2**
2009-10 **(एनएसएस 66वां दौर)**	**1.6**	**1.6**	**2.8**	**5.7**
2004-05 **(एनएसएस 61वां दौर)**	**1.6**	**1.8**	**3.8**	**6.9**
1999-00 **(एनएसएस 55वां दौर)**	**1.7**	**1.0**	**4.5**	**5.7**
1993-94 **(एनएसएस 50वां दौर)**	**1.4**	**0.9**	**4.1**	**6.1**
1987-88 **(एनएसएस 43वां दौर)**	**1.8**	**2.4**	**5.2**	**6.2**
1983 **(एनएसएस 38वां दौर)**	**1.4**	**0.7**	**5.1**	**4.9**
1977-78 **(एनएसएस 32वां दौर)**	**1.3**	**2.0**	**5.4**	**12.4**
1972-73 **(एनएसएस 27वां दौर)**	**1.2**	**0.5**	**4.8**	**6.0**

*(टिप्पणीः *तुलना हेतु, एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व के दौरों के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 31.05.2019 तक, योजना ने 1,51,579 प्रतिष्ठान तथा 1.21 करोड़ लाभार्थी शामिल कर लिए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए थे।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों के लिए आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****